

Financial assistance from European Economic Community to Poverty Alleviation Sector

4824. DR. SANJAYA SINH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the total value of assistance received, till date from the European Economic Community;

(b) what is the amount, out of this total assistance, allotted for the component Project in Poverty Alleviation Sector; and

(c) The manner in which the assistance was utilised for the Poverty Alleviation Sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) (c) Information is being collected.

Allocation for Employment Generation in Rural Areas

4825. SHRI RANJAN PRASAD YADAV: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have allocated Rs. 500 crores or generating employment in rural areas; and

(b) if so, the details of the target groups and nodal agency for implementation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No, Sir. However a sum of Rs. 2046 crores have been provided as Central share of funds under Jawahar Rozgar Yojana (JRY) during 1992-93 with the primary objective of generating employment in rural areas.

(b) The target group under JRY is the people below the poverty line and preference is given to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and freed bonded labourers under the Yojana. The Yojana is being implemented by the District Rural Development Agencies/Zila Parishad and the Village Panchayats at District/Village level respectively.

गरीबी दूर करने संबंधी कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय विकास की अवधारणा

4826. श्री विनोद शर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में गरीबी दूर करने के लिए गरीबी दूर करने संबंधी कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय विकास की अवधारणा को लागू किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत देश में कौन-कौन से राज्य में योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है ;

(ग) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) यह योजना डीसा में कालाहांडी और कोरापुट जिलों में भागों में 1988-89 से दो वर्ष के लिए क्रियान्वित की गई थी ।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार दो वर्ष की परियोजना अवधि (31-3-90 तक) के अन्त तक योजना के तहत 2191.72 लाख रुपये के परिव्यय की तुलना में 1857.52 लाख रुपये खर्च किए गए थे । योजना के विभिन्न घटकों के वृहत वन रोपण का छोड़कर लक्ष्यों की उपलब्ध संतोषजनक थी ।

तत्तश्चात् उड़ीसा सरकार ने कार्यक्रम के "चलती फिरती स्वास्थ्य इकाई" और "पोषाहार" पहलुओं से संबंधित एक मूल्यांकन अद्ययन किया। मूल्यांकन रिपोर्ट में योजना अवधि के दौरान लाभार्थियों के रहने के स्तर में सुधार करने में इन दो क्षेत्रीय कार्यक्रमों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है।

गुजरात में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे किसान

4827. श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने किसान गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं ;

(ख) इन किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन योजना के अंतर्गत अभी तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच. पटेल) : (क) गुजरात

में गरीबी की रेखा से नीचे बस कर ले वाले किसानों की संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 43वें दौर (1987-88) के आधार पर गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 21.2 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे।

(ख) और (ग) किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अलग से कोई योजना नहीं है। तथापि, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना जैसे गरीबी उन्मूलन के प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य छोटे तथा सीमांत किसानों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/मुक्त बंधुवा मजदूरों आदि जैसे समाज के उपेक्षित वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना है इन वर्गों के लोगों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार के अवसर प्रदान कि जाते हैं जबकि जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य इन्हें मजदूरी रोजगार मुहैया कराना है।

1991-92 के दौरान गुजरात राज्य में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निष्पादन निम्न-लिखित अनुसार रहा है :—

कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवारों की संख्या)	68,227	72,326	106 प्रतिशत
जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रम दिन)	244.25	254.13	104 प्रतिशत

Land Reforms in Gujarat

4828. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose

to provide special assistance to Gujarat for implementing land reforms;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?